

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम०के० सिंह
सदस्य

निगरानी प्र० क० 796-दो/2012 विरुद्ध आदेश दिनांक 28-03-12 पारित
आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 109/10-11 अपील.

राशिद खॉ पुत्र निहाल खॉ, मुसलमान
निवासी ग्राम गोरा, तह० मुगांवली,
जिला अशोकनगर, म०प्र०
विरुद्ध

— आवेदक

- 1- अयूब खॉ पुत्र इशाक मोहम्मद
2- रसीद खॉ पुत्र बसीरखॉ
दोनों निवासी ग्राम गोरा, तह० मुगांवली,
जिला अशोकनगर, म०प्र०

— अनावेदकगण

श्री के०के० द्विवेदी, अभिभाषक – आवेदक
श्री दिलीप प्यासी, अभिभाषक – अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक १० जून २०१४, २०१४ को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के अपील प्रकरण क्रमांक 109/10-11 में पारित आदेश दिनांक 28-03-12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बाबरौद स्थित भूमि सर्वे क० 404/2/क रकबा 0.505 है. एवं 405/1 रकबा 0.029 कुल किता 2 कुल रकबा 0.534 है. गजराजसिंह पुत्र हरप्रसाद से आवेदक राशिद खॉ मुसलमान द्वारा पंजीयत विक्रयपत्र दिनांक 27-11-2010 द्वारा क्रय करने के कारण ग्राम पंचायत ने ठहराव क्र. 3 आदेश दिनांक 20-12-10 द्वारा विक्रेता के बजाय क्रेता का नाम अंकित करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदकगण अयूब खॉ एवं रसीद खॉ द्वारा अपील

29-01-11 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 11-08-11 में यह निष्कर्ष निकाला कि विक्रेता महाराजसिंह पुत्र तखतसिंह दांगी ने अपना हिस्सा केता रामरतन पुत्र भगवानसिंह ठाकुर को पंजीयत विक्रयपत्र दिनांक 23-6-64 द्वारा विक्रय किया। तत्पश्चात रामरतन द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीयत विक्रयपत्र दिनांक 13-08-1985 द्वारा अनावेदकों अयूबखाँ आदि को विक्रय की। इन विक्रयपत्रों के आधार पर केतागण का नामान्तरण भी स्वीकार किया गया, किन्तु नामान्तरण आदेश का अमल राजस्व अभिलेख में नहीं होने से अनावेदकों अयूबखाँ आदि ने अमल करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया। सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 के अनुसार वाद के लम्बित होने के दौरान भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता था। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत का नामान्तरण आदेश निरस्त किया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील विव्दान आयुक्त दिनांक 13-8-85 को विक्रय करने के बाद उसे दुबारा विक्रय करने का अधिकार नहीं था। अतः आयुक्त द्वारा अपील खारिज की गयी है। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने अधीनरथ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक ने लिखित तर्कों में यह मुद्दा प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत इश्तहार प्रकाशित कर आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी थी, किन्तु कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने से विचारण न्यायालय ने पंजीयत विक्रयपत्र के आधार पर विक्रेता के स्थान पर केता के नामान्तरण के आदेश दिये हैं। उनका तर्क है कि भूमि के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी थानसिंह, गजराजसिंह, बहादुरसिंह, प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी थानसिंह, गजराजसिंह, बहादुरसिंह, शेरसिंह पुत्रगण हरप्रसाद थे जिनका नाम राजस्व अभिलेख में विधिवत अभिलिखित था। अभिलिखित भूमिस्वामी द्वारा आवेदक के पक्ष में पंजीयत विक्रयपत्र दिनांक 27-11-2010 निष्पादित किया है और इसके आधार पर ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव कर्मांक 3 आदेश दिनांक 20-12-2010 द्वारा नामान्तरण स्वीकृत किया है जिसमें कोई विधिक

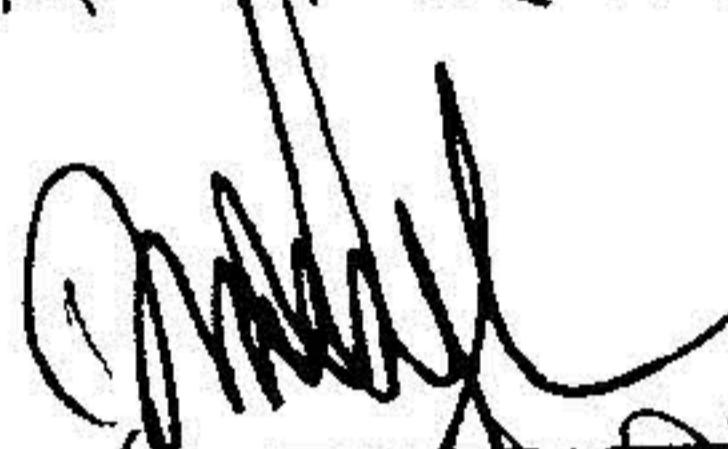
त्रुटि नहीं थी। अनावेदकगण द्वारा भूमि रामरतनसिंह पुत्र भगवानसिंह दांगी से विक्रयपत्र द्वारा खरीदना बताया है, किन्तु रामरतन सिंह पुत्र भगवानसिंह दांगी का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में कभी भी अभिलिखित नहीं था। ऐसी दशा में उन्हें भूमि विक्रय करने का वैधानिक अधिकार नहीं था। उनका यह भी तर्क है कि अनावेदकगण विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं थे और ना ही उन्होंने अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति अपीलीय अनुविभागीय अधिकारी से ली गयी, इसलिये अपील प्रचलन योग्य नहीं थी। रामरतन पुत्र भगवानसिंह दांगी द्वारा भूमि का विक्रयपत्र महाराजसिंह द्वारा दिनांक 23-03-1984 को कराया जाना बताया गया है, जबकि उक्त विक्रयपत्र महाराजसिंह द्वारा सम्पादित नहीं कराया गया, बल्कि महाराजसिंह के स्थान पर अन्य किसी फर्जी व्यक्ति को खड़ाकर सम्पादित कराया गया है। इस संबंध में उनका यह भी तर्क है कि सह-खाते की भूमि होने से महाराजसिंह को सह-खातेदारों की सहमति के बिना प्रश्नाधीन भूमि विक्रय की अधिकारिता नहीं थी। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक ने लिखित तर्कों में मुख्य रूप से यह मुद्दा प्रस्तुत किया है कि तहसीलदार मुगांवली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-3-96 तथा आदेश दिनांक 27-03-91 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अनावेदकगण के नाम नामान्तरण किये जाने के आदेश पारित किये गये, किन्तु इन आदेश के विरुद्ध गजराजसिंह द्वारा किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गयी, इस कारण यह अंतिम हो चुके हैं। राजस्व अभिलेख में अमल न करने के कारण इस स्थिति का लाभ उठाकर प्रकरण लम्बित रहते हुए गजराजसिंह द्वारा अधिकार नहीं होते हुए भी भूमि आवेदक को दिनांक 27-11-10 को विक्रय की गयी है जिस पर से कोई स्वत्व केता को प्राप्त नहीं होते। अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त ने समर्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत विचार कर आदेश पारित किये हैं। उनका यह भी तर्क है कि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के प्रावधानानुसार वाद लम्बित होने के समय भूमि क्य करने पर केता को भूमिस्वामी के रूप में कब्जेदार नहीं माना जा सकता। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख में उपलब्ध खसरा पंचसाला संवत् 2050 लगायत 2054 में सर्वे नं० 390 रकबा 8.109 हरप्रसाद पुत्र फुन्दीलाल 16 न.पैसा, गजराजसिंह पुत्र हरप्रसाद 23 न.पैसा, नथूसिंह पुत्र तखतसिंह 31 न.पैसा, बहादुरसिंह 0.07, मचलसिंह .07, शेरसिंह .06, थानसिंह .10 पुत्रगण हरप्रसाद भूमिस्वामी के रूप में 0.07, मचलसिंह .07, किश्तबन्दी खतौनी संवत् 2047 (वर्ष 1990-91) में प्रश्नाधीन भूमि अन्य अंकित है। किश्तबन्दी खतौनी संवत् 2047 (वर्ष 1990-91) में प्रश्नाधीन भूमि अन्य भूमियों के साथ उपरोक्तानुसार सहखातेदारों के नाम अभिलिखित है। अनुविभागीय भूमियों के साथ उपरोक्तानुसार सहखातेदारों के नाम अभिलिखित है। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख पृष्ठ 57 पर उपलब्ध नामान्तरण पंजी क्र० 49 आदेश दिनांक 5-4-94 द्वारा सहखातेदारों की सहमति से पटवारी द्वारा प्रस्तुत बटवारा रखीकृत कर एडिशनल तहसीलदार द्वारा अभिलेख संशोधन के आदेश दिये हैं, इस आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के संबंध में कोई प्रमाण अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि वर्ष 1985 में प्रश्नाधीन भूमि न्यायालयों के साथ सहखाते में दर्ज थी और सह-खातेदारों के मध्य भूमि का अन्य भूमियों के साथ सहखाते में दर्ज थी और सह-खातेदारों के विशेष सर्वे क्रमांक विक्रय विधिवत बटवारा नहीं हुआ था, इस कारण सहभूमिस्वामी को विशेष सर्वे क्रमांक विक्रय की अधिकारिता नहीं थी, सिर्फ सहभूमिस्वामी द्वारा अपने हिस्से का विक्रय किया जा सकता था। अनावेदकगण अयूब खँ एवं रशीदखँ द्वारा विक्रेता रामरतन पुत्र भगवानसिंह से प्रश्नाधीन भूमि पंजीयत विक्रयपत्र दिनांक 13-08-85 से खरीदी है, किन्तु विक्रेता रामरतन पुत्र भगवानसिंह का नाम राजस्व अभिलेख खसरा पंचसाला आदि में भूमिस्वामी के रूप में अंकित होने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके विपरीत आवेदक रासिदखँ पुत्र निहाल खँ द्वारा प्रश्नाधीन भूमि राजस्व के संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय द्वारा नामान्तरण रूप के संबंध में संक्षिप्त जॉच के पश्चात किये जाते हैं, इस कारण अनावेदकगण अयूबखँ एवं रशीदखँ को पंजीयत विक्रयपत्र दिनांक 13-08-85 के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर कोई रूपत्व प्राप्त हैं तो उन्हें सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर घोषित कराना चाहिये थे, किन्तु अपीलीय न्यायालयों ने आदेश पारित करते समय इस ओर कोई ध्यान

नहीं दिया। राजस्व न्यायालय को पंजीयत विक्रयपत्र को शून्य या निष्प्रभावी घोषित करने की अधिकारिता नहीं है। ऐसी दशा में अभिलिखित भूमिस्वामी से आवेदक रासिदखाँ द्वारा पंजीयत विक्रयपत्र से भूमि खरीदने के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामान्तरण करने में ग्राम पंचायत द्वारा कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं की गयी थी।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। आयुक्त का आदेश दिनांक 28-03-12 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 11-08-11 निरस्त किये जाते हैं। परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत बावरौद का ठहराव क्र0 3 आदेश दिनांक 20-12-10 यथावत रखा जाता है।



एम०क०सिंह)

सदस्य,
राजस्व मण्डल, म०प्र०
गवालियर,